अंक-1

स्वास्थ्य आपके द्वार...

मासिक न्यूज़लेटर | जनवरी, 2026

अपर मुख्य सचिव की कलम से...

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विभागीय मासिक पत्रिका "स्वास्थ्य आपके द्वार" के प्रथम संस्करण का प्रकाशन प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली में हुए सुधारों, कार्यक्रमों की प्रगति एवं परिणामोन्मुखी प्रयासों को साझा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

विगत वर्षों में प्रदेश ने स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार किया है। विभाग के अथक प्रयासों का परिणाम है कि प्रदेश में वर्ष 2013 की तुलना में नवजात मृत्यु दर में 25 प्रतिशत एवं मातृ मृत्यु दर में 60 प्रतिशत की कमी आयी है। अर्जित उपलब्धियाँ नीतिगत प्रतिबद्धता, सुदृढ़ कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा धरातल पर स्वास्थ्यकर्मियों के समर्पित प्रयासों का प्रतिफल है।

यद्यपि यह प्रगति उत्साहवर्धक है, तथापि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु और अधिक संगठित एवं लक्षित प्रयासों की आवश्यकता है।

इस दिशा में डेटा आधारित निर्णय, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों का प्रभावी उपयोग, गुणवत्ता मानकों का सुदृढ़ अनुपालन तथा जवाबदेही आधारित कार्य संस्कृति को मजबूत किया जाना आवश्यक है।

यह विभागीय मासिक पत्रिका नीति, क्रियान्वयन एवं परिणामों के मध्य एक प्रभावी संवाद मंच के रूप में कार्य करेगी तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में सतत सुधार की प्रक्रिया को गति प्रदान करेगी।

मैं, मासिक पत्रिका के प्रकाशन की इस पहल से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करता हूं तथा इसके नियमित, तथ्यपरक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रकाशन हेतु शुभकामनाएं देता हूं।

धन्यवाद।

अमित कुमार घोष आई0ए0एस0
अपर मुख्य सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
व चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0

मिशन निदेशक की कलम से...

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रकाशित विभागीय मासिक पत्रिका "स्वास्थ्य आपके द्वार" के प्रथम अंक के प्रकाशन के अवसर पर मैं समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वास्थ्यकर्मियों, सहयोगी संस्थाओं तथा प्रदेश के सम्मानित स्वास्थ्य लाभार्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित करती हूं।

यह मासिक पत्रिका चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों, नवाचारों, उपलब्धियों एवं श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को साझा करने का एक सशक्त और प्रेरणादायी मंच सिद्ध होगी। यह न केवल 'नीति निर्माण, प्रभावी क्रियान्वयन एवं ठोस परिणामों के मध्य एक सुदृढ़ सेतु का कार्य करेगी, बल्कि विभागीय प्रयासों को एक साझा दृष्टि, उद्देश्य और उर्जा भी प्रदान करेगी।

इस पत्रिका के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य, पोषण, संचारी एवं गैर-संचारी रोगों की रोकथाम सहित जन स्वास्थ्य से जुड़े सभी महत्वपूर्ण आयामों की समेकित, प्रामाणिक एवं अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को सशक्त निर्णय लेने तथा बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

प्रदेश सरकार की नीतिगत प्रतिबद्धता के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, समावेशी, गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।

यह मासिक पत्रिका आम जन तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुदृढ़ करने हेतु किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों, नवाचारों एवं समर्पित प्रयासों को व्यापक पहचान प्रदान करेगी तथा ज़मीनी स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों को और अधिक निष्ठा, संवेदनशीलता एवं उत्साह के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित करेगी।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह विभागीय मासिक पत्रिका ज्ञान-साझाकरण, आपसी समन्वय, संस्थागत सुदृढ़ीकरण एवं उत्कृष्टता की संस्कृति को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा "स्वस्थ उत्तर प्रदेश" के हमारे साझा संकल्प को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी।

मैं इस मासिक पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सतत प्रयासों की सराहना करती हूँ तथा इसके सफल, नियमित एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रकाशन हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करती हूँ।

धन्यवाद।

डॉ0 पिंकी जोवल आई.ए.एस.
मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
व सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उ0प्र0

"सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया।"

उत्तर प्रदेश में मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हो रही निरंतर प्रगति

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थापित सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों में चिन्हित कुल 6654 प्रसव केन्द्रों की तुलना में दिसंबर, 2025 में 5936 प्रसव केन्द्रों पर सुरक्षित प्रसव कराए गए। इसके अलावा कुल 427 प्रसव केन्द्रों को एफ.आर.यू. के रूप में चिन्हित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह दिसंबर, 2025 तक 379 एफ.आर.यू. क्रियाशील हैं।

जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आशा एवं लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर माह तक तक प्रदेश में कुल 18,16,091 संस्थागत प्रसव कराए गए। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क परिवहन, निःशुल्क जांच, निःशुल्क औषधि, निःशुल्क भोजन तथा आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके तहत कुल 54,25,094 महिलाओं को निःशुल्क औषधि, 13,52,508 महिलाओं को निःशुल्क भोजन तथा 50,00,050 महिलाओं को निःशुल्क जांच की सुविधा प्रदान की गई।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिसंबर, 2025 तक)

प्रदेश की **2128** स्वास्थ्य इकाइयों पर

कुल **76,608**

मातृत्व जाँच शिविर आयोजित

हर महीने

01 09 16 24

तारीख को

3,45,591

उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान

एनएचएम के इन प्रयासों के माध्यम से प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक

सुलभ, सुरक्षित एवं प्रभावी

बनाया जा रहा है।

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम: नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह अप्रैल-दिसम्बर 2025 तक लक्षित 43,86,886 लाभार्थियों की तुलना में एचएमआईएस डाटा के अनुसार कुल 43,72,692 (99.68 प्रतिशत) बच्चों को पूर्ण प्रतिरक्षित किया गया।

परिवार नियोजन कार्यक्रम: माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार परिवार नियोजन कार्यक्रम लक्ष्य मुक्त है। वर्ष 2025-26 में माह दिसम्बर 2025 तक परिवार नियोजन के स्थायी एवं अस्थायी विधा के कुल 33,68,508 लाभार्थियों को सेवा प्रदान की गयी।

टीबी उन्मूलन की दिशा में उत्तर प्रदेश की बड़ी सफलता

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जनवरी से दिसम्बर 2025 तक निर्धारित 6.75 लाख लक्ष्य के सापेक्ष 6.77 लाख टीबी मरीजों का पंजीकरण किया गया, जो 103 प्रतिशत है। इसके साथ ही, टीबी मरीजों को पोषण सहायता देने के लिए डीबीटी के माध्यम से अप्रैल 2018 से दिसम्बर 2025 तक 31.43 लाख मरीजों को 1021.86 करोड़ रुपये दिए गए। वर्ष 2025 में ही 2.99 लाख मरीजों को 141.72 करोड़ रुपये की सहायता मिली। प्रदेश में टीबी की समय पर पहचान और बेहतर इलाज के लिए जांच सुविधाओं को मजबूत किया

गया है। वर्तमान में 930 नैट मशीनों और 14 कल्चर डीएसटी प्रयोगशालाओं से संभावित टीबी रोगियों को निःशुल्क आधुनिक जांच सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा निक्षय मित्र पहल के तहत 96 हजार से अधिक लोगों ने 7.41 लाख मरीजों को पोषण पोटली प्रदान की गई।

प्रदेश के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है। 24 मार्च 2025 को विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही वर्ष 2024 में प्रदेश की 7,191 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। ये उपलब्धियां प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम हैं।

ब्लड सेवाओं के माध्यम से सुरक्षित रक्त आपूर्ति और विशेष रोगियों को राहत

प्रदेश में थैलेसीमिया रोगियों की देखभाल के लिए 29 केन्द्रों के माध्यम से थैलेसीमिया रोगियों को तथा 26 केन्द्रों के माध्यम से हीमोफीलिया रोगियों को निःशुल्क परामर्श, जांच और औषधि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त 10 केन्द्रों में हाइ परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी (एचपीएलसी) उपकरणों की स्थापना के माध्यम से हिमोग्लोबीन वैरिएंट की जांच की सुविधा प्रदान की जा रही है। साथ ही नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सात जनजातीय बहुल जनपदों बहराइच, बलिया, देवरिया, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, ललितपुर एवं सोनभद्र में जनजातीय आबादी का निःशुल्क सिकल सेल परीक्षण एवं उपचार किया जा रहा है। इन प्रयासों के माध्यम से प्रदेश में सुरक्षित रक्त उपलब्धता और रोगियों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवंबर माह तक प्रदेश में ब्लड सर्विसेज एवं ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट के तहत प्राप्त की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार है -

क्र.सं.	विवरण	उपलब्धि
1.	राजकीय रक्त केन्द्रों द्वारा संग्रहित कुल यूनिट	6,01,659 यूनिट
2.	स्वैच्छिक रक्तदान के माध्यम से संग्रहित कुल यूनिट	3,50,180 यूनिट
3.	स्वैच्छिक रक्तदान	58%
4.	रक्तदान शिविरों के माध्यम से संग्रहित कुल यूनिट	52,011 यूनिट
5.	ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेशन इकाइयों द्वारा निर्मित कुल ब्लड कम्पोनेंट	5,19,919 यूनिट
6.	ब्लड कम्पोनेन्ट सेपरेशन इकाइयों में ब्लड कम्पोनेंट	86%
7.	बीसीटीवी के माध्यम से संग्रहित कुल यूनिट	32,281 यूनिट

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत लाखों बच्चों को मिला ससमय उपचार

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में बच्चों के स्वास्थ्य की समय पर पहचान और उपचार के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 3.52 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में 252.96 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रसव केंद्रों पर जन्मे नवजात शिशुओं में जन्मजात दोषों की पहचान के लिए 15.85 लाख शिशुओं की स्वास्थ्य जांच की गई। चार प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं जन्मजात दोष, पोषक तत्वों की कमी, बीमारियों और विकास में देरी से प्रभावित 13.61 लाख रेफर किए गए बच्चों में से 11.66 लाख बच्चों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश में संचालित 12 डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (डीईआईसी) में कुल 34,482 बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। इनमें से विकास में देरी एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित 14,621 बच्चों का उपचार एवं प्रबंधन किया गया।

मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों एवं चिकित्सालयों में चिन्हित गंभीर जन्मजात रोगों जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जन्मजात मोतियाबिंद, दृष्टि एवं श्रवण बाधा, जन्मजात एवं रूमेटिक हृदय रोग, ओटाइटिस मीडिया, कटे होंठ-तालु, टेढ़े पैर (क्लब फुट) सहित अन्य जटिल स्थितियों से ग्रसित 6,085 बच्चों की सर्जरी और आवश्यक स्वास्थ्य प्रबंधन किया गया। इन प्रयासों के माध्यम से प्रदेश में बच्चों के स्वस्थ विकास और बेहतर भविष्य की दिशा में सशक्त कदम उठाए जा रहे हैं।

उपचार से पहले

उपचार के बाद

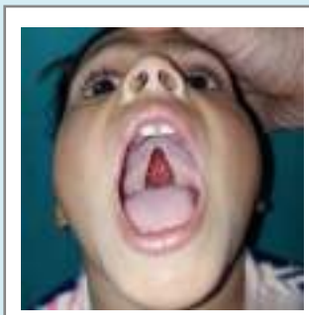

उपचार से पहले

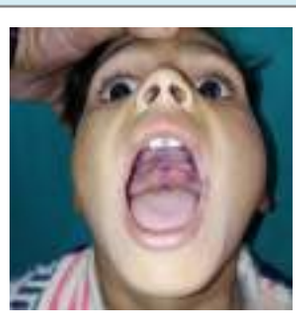

उपचार के बाद

आईडीएसपी के तहत रोग निगरानी एवं आउटब्रेक नियंत्रण में मजबूती

आईडीएसपी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में आउटब्रेक उन्मुख बीमारियों की प्रभावी निगरानी की जा रही है, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सिन्ड्रोमिक, प्रीजम्पटिव और लैब आधारित रिपोर्टिंग से समय पर विश्लेषण और कार्रवाई संभव हो रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल से दिसम्बर 2025 तक फॉर्म-एस की औसत साप्ताहिक रिपोर्टिंग 82.48 प्रतिशत, फॉर्म-पी की 54.79% और फॉर्म-एल की 91.71 प्रतिशत रही। यूडीएसपी पोर्टल से आईएचआईपी/आईडीएसपी पोर्टल पर एपीआई लिंकेज के कारण रिपोर्टिंग में निरंतर सुधार दर्ज किया गया है। इसी अवधि में कुल 121 आउटब्रेक रिपोर्ट किए गए, जिनमें 70.24 प्रतिशत मामलों में लैब सुविधा उपलब्ध रही, जबकि चिकनपॉक्स, फूड व मशरूम प्वाइजनिंग को छोड़कर 91 आउटब्रेक्स में से 82.41 प्रतिशत में लैब आधारित जांच के साथ त्वरित नियंत्रण कार्रवाई की गई।

वेक्टर जनित रोगों पर प्रभावी नियंत्रण, मृत्यु दर शून्य

राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न डिजीज नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में एईएस/जेई और मलेरिया पर प्रभावी नियंत्रण के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। 1 जनवरी से 31 दिसम्बर 2025 तक एईएस के 694 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 63 जेई रोगी शामिल हैं, जबकि वर्ष 2017 में 13 प्रतिशत से अधिक रही एईएस और जेई की मृत्यु दर 31 दिसम्बर 2025 तक घटकर 3% हो गई है। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दिसम्बर 2025 तक 1.86 करोड़ से अधिक जांचें की गईं, जिनमें 14,590 मरीज पॉजिटिव पाए गए और सभी का पूर्ण उपचार किया गया। इसके मुकाबले वर्ष 2024 की समान अवधि में 1.45 करोड़ जांचों में 13,477 मामले सामने आए थे। ये आंकड़े प्रदेश में वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम में मजबूत निगरानी और समय पर उपचार की सफलता को दर्शाते हैं।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम से कुष्ठ रोग के मामलों में लगातार कमी

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में कुष्ठ रोग की समय पर पहचान और उपचार को सशक्त किया जा रहा है। सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क एमडीटी दवाएं उपलब्ध हैं तथा आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा रोगियों की पहचान, संदर्भन और उपचार पूर्ण कराने पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दिसम्बर 2025 तक कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं - अवशेष अभिलेखित कुष्ठ रोगियों की संख्या दिसम्बर 2024 के 9,781 से घटकर 8,202 रह गई है। नये रोगी खोजी दर 5.36 से घटकर 4.24 प्रति एक लाख जनसंख्या तथा कुष्ठ रोग की व्यापकता दर 0.40 से घटकर 0.33 प्रति 10,000 जनसंख्या हो गई है। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर विकलांगता दर भी 0.16 से घटकर 0.14 हो गई है, जो कार्यक्रम की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

किशोर मानसिक स्वास्थ्य: TeleMANAS टोल फ्री नं. एवं ऐप के माध्यम से समय पर परामर्श और सहयोग

किशोरावस्था में मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ आम होती हैं जिनके प्रमुख कारण पढ़ाई का दबाव, सामाजिक अपेक्षाएँ, स्वयं की पहचान, भावनात्मक उतार चढ़ाव और बढ़ते डिजिटल मीडिया के प्रभाव हैं। इन कारणों से युवा पीढ़ी अक्सर तनावग्रस्त रहती हैं। कई बार वे अकेलापन, चिंता या अवसाद का अनुभव करते हैं। ऐसे समय में परिवार, मित्र और शिक्षकों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। खुली बातचीत, सहानुभूति और सुरक्षित वातावरण किशोरों को अपनी भावनाएँ साझा करने में मदद करता है। साथ ही, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता एवं ससमय परामर्श सेवाएँ उन्हें सही दिशा दिखा सकते हैं।

अतः किशोरों को भी याद रखना चाहिए कि मदद माँगना कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने की दिशा में एक साहसी कदम है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के सहयोग से स्वास्थ्य इकाईयों एवं स्कूलों में Tele MANAS ऐप और हेल्पलाइन नंबर 14416 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा हैं। Tele MANAS सेवाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित परामर्शदाता द्वारा टेलीफोन नं0 एवं ऐप के माध्यम से मानसिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

वीडियो देखने के लिए दिए गए QR Code स्कैन करें

टोल फ्री नं. 14416/1800-891-4416

उत्तर प्रदेश शासन | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश | सहयोग: UP-TSU, ihat

Follow us on x.com/nhm_up youtube.com/NHMUPIEC nhm.up

अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएँ nhmiec@gmail.com पर मेल करें।